



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

CRMP No. 623/2024

1. मोहम्मद आदिल भोजानी, आ. मोहम्मद अमीन भोजानी,  
उम्र-34 वर्ष, निवासी-R/o-401, मुजफ्फर रेजिडेंसी,  
नियर एस.बी. कॉलोनी, मेहदीपटनम,  
हैदराबाद सिटी, तेलंगाना .....याचिकाकर्ता

//बनाम//

1. छत्तीसगढ़ राज्य  
द्वारा जिला मजिस्ट्रेट रायपुर छत्तीसगढ़
2. आफरीन सोना, पति- मोहम्मद आदिल भोजानी  
निवासी-R/o दाऊ बाड़ा, फर्स्ट फ्लोर,  
नया पारा, गोलबाजार रायपुर,  
जिला- रायपुर छत्तीसगढ़. .... उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से श्रीमती फौजिया मिर्जा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नवीन शुक्ला,  
अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक-1 राज्य श्री वाई.एस.ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक-2 की ओर से श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।



**माननीय न्यायमूर्ति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल, न्यायमूर्ति**  
**बोर्ड पर आदेश**

**10.05.2024**

1. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जो 26.02.2024 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (सीबीआई मामलों के विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश), रायपुर द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 89/2024 में पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसमें 13.02.2024 को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर द्वारा पारित आदेश को पुष्ट किया गया था।
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि, शिकायतकर्ता/उत्तरवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता के साथ 09.10.2021 को उनके रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ और अंततः शिकायतकर्ता ने 20.01.2024 को याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज की, जिस पर महिला पुलिस थाना, रायपुर में आईपीसी की धारा 377, 498-ए, 34, 323, 506 और 354-ए तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत अपराध संख्या 13/2024 का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्तमान याचिकाकर्ता मोहम्मद आदिल भोजानी, उसके पिता मोहम्मद अमीन भोजानी, माता शहनाज भोजाई और उसकी बहनें अन्जु फिरदोस और नाज फातिमा के विरुद्ध दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता मोहम्मद आदिल भोजानी और उसके पिता मोहम्मद अमीन भोजानी को 21.01.2024 को आरोपित अपराध में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 24.01.2024 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। याचिकाकर्ता और उसके पिता ने सत्र न्यायालय, रायपुर के समक्ष धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत आवेदन दायर किया, जिसे जमानत आवेदन संख्या 259/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया और इसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/सीबीआई मामलों के विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में विचार के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त जमानत आवेदन की



सुनवाई 24.01.2024 को की गई और पक्षों को सुनने के बाद, उनका जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता और उसके पिता को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया।

- “1. याचिकाकर्ता और उसके पिता को जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और मामले की सुनवाई में सहयोग करें।
2. याचिकाकर्ता और उसके पिता को भारत से बाहर यात्रा करने से पहले न्यायालय से अनुमति लेनी होगी।
3. याचिकाकर्ता और उसके पिता को मामले की जांच में सहयोग करना होगा और चार्जशीट दाखिल होने तक उपस्थित रहना होगा।
4. याचिकाकर्ता और उसके पिता को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।”

3. विशेष न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता को जमानत देते समय शर्त संख्या 4 यह थी कि वह भारत से बाहर यात्रा नहीं करेगा। याचिकाकर्ता ने जेएमएफसी, रायपुर के समक्ष भारत से बाहर यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें यह आधार दिया गया कि याचिकाकर्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है और सिंगापुर में नियोजित है और उसे 14.02.2024 से भारत से बाहर यात्रा करने की आवश्यकता है और वह 08.03.2024 को वापस लौटेगा और यदि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसकी नौकरी जा सकती है। याचिकाकर्ता के उक्त आवेदन पर 09.02.2024 को विचार किया गया और पक्षों को सुनने के बाद, जेएमएफसी, रायपुर ने याचिकाकर्ता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन के साथ अपनी नौकरी या रोजगार से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है और मामले की जांच अधूरी है और चार्जशीट अभी दाखिल नहीं की गई है, इसलिए याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है।





4. फिर 13.02.2024 को याचिकाकर्ता ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए एक और आवेदन दायर किया, जिसमें यह कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा 08.02.2024 को विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दायर पिछला आवेदन 09.02.2024 को अदालत द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदन के साथ रोजगार से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता टी-सिस्टम सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के साथ कार्यरत है और अब उसे सिंगापुर में काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वह अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर रहा है। उसने यह भी कहा कि उसे 14.02.2024 को सिंगापुर जाना है और 07.03.2024 को वापस आना है। यह भी कहा गया कि यदि वह आदेशों का पालन नहीं करेगा और सिंगापुर नहीं जाएगा तो उसकी नौकरी जा सकती है।

5. याचिकाकर्ता के आवेदन पर 13.02.2024 को ही विचार किया गया और पक्षों को सुनने के बाद इसे फिर से खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि 09.02.2024 को याचिकाकर्ता का आवेदन पहले ही खारिज कर दिया गया था; जांच अभी चल रही है; आवेदक की उपस्थिति जांच के दौरान आवश्यक है और चार्जशीट अभी दाखिल नहीं की गई है।

6. दिनांक 13.02.2024 के आदेश को याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय, रायपुर में पुनरीक्षण दायर करके चुनौती दी, जिसे अंततः अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/सीबीआई मामलों के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 89/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया। शिकायतकर्ता ने विशेष न्यायालय में दायर उक्त आपराधिक पुनरीक्षण में आपत्ति उठाई। आपराधिक पुनरीक्षण की सुनवाई 26.02.2024 को हुई और पक्षों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश ने पुनरीक्षण को खारिज कर दिया, यह कहते हुए



कि याचिकाकर्ता जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में नियोजित है, उसका भारत में पुणे में एक शाखा कार्यालय है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त सॉफ्टवेयर कंपनी याचिकाकर्ता से केवल सिंगापुर कार्यालय में काम लेना चाहती है। आदेश में यह भी देखा गया कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने बहरीन में नौकरी छोड़ने के बाद टी-सिस्टम कंपनी में नौकरी प्राप्त की है, जिसमें वह वर्तमान में नियोजित है। यह भी देखा गया कि याचिकाकर्ता के माता-पिता के पास हैदराबाद में चल और अचल संपत्ति है और इसलिए, यदि याचिकाकर्ता की नौकरी चली भी जाती है, तो उसकी आजीविका का प्रश्न नहीं उठेगा क्योंकि वह दूसरी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, जांच अधूरी है और याचिकाकर्ता को जमानत देते समय जारी निर्देशों के अनुसार कि वह जांच में सहयोग करेगा और यदि उसे विदेश जाने की अनुमति दी जाएगी, तो उसके लिए जांच में सहयोग करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, सिंगापुर और भारत के बीच किसी भी आरोपी को मुकदमे के दौरान या दोषसिद्धि के बाद भारत सरकार को सौंपने के लिए कोई संधि नहीं है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण को विशेष न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया है, जो वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

7. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को 21.01.2024 को गिरफ्तार किया गया था और उसे 24.01.2024 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसमें उस पर कुछ शर्तें लगाई गई थीं कि जब भी याचिकाकर्ता बाहर जाएगा, वह अदालत से पूर्व अनुमति लेगा और बिना पूर्व अनुमति के वह भारत से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 24.01.2024 के आदेश का पालन करते हुए याचिकाकर्ता ने अपने रोजगार के लिए विदेश यात्रा की पूर्व अनुमति के लिए आवेदन दिया था। याचिकाकर्ता का आवेदन पहले इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदन के साथ उसके रोजगार से संबंधित कोई दस्तावेज



संलग्न नहीं किया गया था। जब उसने संबंधित दस्तावेजों के साथ दूसरा आवेदन दिया, तो उसे फिर से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पहले याचिकाकर्ता का आवेदन 09.02.2024 को पहले ही खारिज कर दिया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विदेश यात्रा का अधिकार याचिकाकर्ता का भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। याचिकाकर्ता पर लगाई गई शर्त उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर दबाव डालेगी और उसके विदेश यात्रा के अधिकार को सीमित कर देगी, हालांकि राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और इसके अलावा कि मामला याचिकाकर्ता की आजीविका और रोजगार से संबंधित है, याचिकाकर्ता पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए और/या उसे अपनी आजीविका और रोजगार के उद्देश्य से विदेश यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए।

8. याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस बीच जांच पूरी हो चुकी है और मामले में चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है। इसलिए, आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को अपने काम के लिए भारत से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

9. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 1 के वकील ने आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि विशेष न्यायाधीश ने 26.02.2024 का आदेश सही ढंग से पारित किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. उत्तरवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि 09.02.2024 के आदेश के दो भाग हैं, यानी याचिकाकर्ता के रोजगार से संबंधित आवेदन के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया था और दूसरा भाग यह है कि जांच अधूरी है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि हालांकि याचिकाकर्ता ने संबंधित दस्तावेजों के साथ विदेश यात्रा की अनुमति के लिए अपना दूसरा आवेदन दायर किया है, लेकिन



दूसरा भाग यानी मामला अभी भी जांच के अधीन है, में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चूंकि, जेएमएफसी, रायपुर द्वारा पहले ही आदेश पारित किया जा चुका है, इसलिए उसी आधार पर बाद के आवेदन पर विचार करना उसके पिछले आदेश की समीक्षा करने के बराबर होगा, जो दंड प्रक्रिया संहिता में अनुमति नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता का आवेदन जेएमएफसी, रायपुर द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाएगी, तो मामले की सुनवाई के दिनों में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना मुश्किल होगा और मुकदमे की कार्यवाही केवल इसी कारण से रुक जाएगी। शर्त केवल याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई थी ताकि मुकदमे में देरी न हो। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता है कि नियोक्ता कंपनी केवल सिंगपुर में उससे काम लेना चाहती है। याचिकाकर्ता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह भारत से ही ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना काम कर सकता है और उसकी वहां शारीरिक उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, पुनरीक्षण न्यायालय और अदालत द्वारा पारित आदेश उचित हैं, जिनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों को सुना है और आदेशों का अवलोकन किया है।
12. चूंकि वर्तमान मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल कर दी गई है, इसलिए यह न्यायालय जांच के लंबित होने के पहलू पर विचार नहीं कर रहा है।
13. श्रीमती मनेका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य, 1978 (1) एससीसी 248 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 35 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया था ।



“35. ... .. ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहां लगाया गया प्रतिबंध सतही तौर पर केवल विदेश यात्रा के अधिकार पर होता है, लेकिन प्रत्यक्ष और अनिवार्य परिणाम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या पेशा चलाने के अधिकार में हस्तक्षेप करना होता है। एक संगीतकार विदेश जाकर गाना चाह सकता है, एक नर्तक नृत्य करना चाह सकता है, एक विजिटिंग प्रोफेसर पढ़ाना चाह सकता है और एक विद्वान किसी सम्मेलन या सेमिनार में भाग लेना चाह सकता है। यदि ऐसे मामले में उसका पासपोर्ट अस्वीकार कर दिया जाता है या जब्त कर लिया जाता है, तो यह उसकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप होगा। यदि किसी अखबार के संवाददाता को विदेशी असाइनमेंट दिया जाता है और उसका पासपोर्ट अस्वीकार कर दिया जाता है या जब्त कर लिया जाता है, तो यह उसके पेशा चलाने की स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप होगा। उदाहरण बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि हालांकि विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, विदेश यात्रा के अधिकार से इनकार करना, सच्चाई में और प्रभाव में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या पेशा चलाने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है, जिससे अनुच्छेद 19 (1) (ए) या 19 (1) (जी) का उल्लंघन हो सकता है।”

14. सतीश चंद्र वर्मा बनाम भारत संघ और अन्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 2048 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 5 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया था।

“5. विदेश यात्रा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मूलभूत मानवाधिकार है क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्र और आत्मनिर्णयात्मक रचनात्मक चरित्र को पोषित करता है, न केवल उसकी कार्यवाही की स्वतंत्रता को बढ़ाकर, बल्कि उसके अनुभव के दायरे को भी बढ़ाकर। यह अधिकार निजी जीवन तक भी फैला हुआ है; विवाह, परिवार और



मित्रता मानवता के ऐसे पहलू हैं जो विदेश यात्रा की स्वतंत्रता से इनकार करने से शायद ही प्रभावित होते हैं और स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह स्वतंत्रता एक वास्तविक मानवाधिकार है। (देखें: श्रीमती मनेका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य (1978) 1 एससीसी 248)। उक्त निर्णय में, जस्टिस डगलस के शब्दों का संदर्भ दिया गया है, जो केंट बनाम डुल्स 357 यूएस 116 में निम्नलिखित हैं।

“विदेश यात्रा की स्वतंत्रता का बहुत सामाजिक मूल्य है और यह महत्वपूर्ण मूलभूत मानवाधिकार का प्रतिनिधित्व करती है।”

15. बरुन चंद्र ठाकुर बनाम रायन ऑगस्टीन पिंटो और अन्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1899 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 9 और 10 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया था:

“9. परिस्थितियों के समग्र परिप्रेक्ष्य में, यह न्यायालय इस राय में है कि चूंकि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, तथ्यों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जो उच्च न्यायालय को अग्रिम जमानत के अनुदान को नियंत्रित करने वाली शर्तों को संशोधित करने के लिए उचित ठहराए। महत्वपूर्ण रूप से, उत्तरवादी द्वारा जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए एक समान आवेदन पहले किया गया था, जो सफल नहीं हुआ था; उसने उस आवेदन को वापस ले लिया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि विदेश यात्रा का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। इसी तरह, हालांकि, विदेश यात्रा से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करने की शर्त एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे निस्संदेह इस मामले में अग्रिम जमानत के अनुदान के लिए एक शर्त के रूप में जोड़ा गया था। ... .. अधिक से अधिक, विदेश यात्रा से पहले अनुमति प्राप्त करने



की शर्त को विनियमित किया जा सकता था, पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता था।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस राय में है कि आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है; इसे तदनुसार रद्द कर दिया जाता है। उत्तरवादी पर लगाई गई शर्त, जो अग्रिम जमानत के अनुदान के आदेश के हिस्से के रूप में विदेश यात्रा से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए थी, को यहां बहाल किया जाता है। साथ ही, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह अनुमति प्राप्त करने के लिए दायर किए गए आवेदन पर, जब भी दायर किया जाए, यथाशीघ्र विचार करे और किसी भी स्थिति में, आदेश आवेदन दाखिल करने के एक सप्ताह के भीतर पारित करे। यह बिना कहे चला जाता है कि ऐसे आदेश सीबीआई के विचार को ध्यान में रखते हुए और प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए पारित किए जाएंगे, और साथ ही, यह सुनिश्चित करते हुए कि यात्रा शुरू करने से पहले उचित समय भी दिया जाए।”

16. परवेज नूरदीन लोखंडवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2020 (10) एससीसी 77 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 19 और 20 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया था:

“19. बरुन चंद्र ठाकुर बनाम रायन ऑगस्टीन पिंटो में, इस न्यायालय ने एक शर्त को बहाल किया, जो उत्तरवादी को विदेश यात्रा से पहले सक्षम न्यायालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य करती थी। यह शर्त, जो मूल रूप से उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत के अनुदान के समय लगाई गई थी, बाद में उसी द्वारा हटा दी गई थी। इस न्यायालय ने आरोपी के विदेश यात्रा के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए:



“9. ... .. यह नहीं कहा जा सकता है कि विदेश यात्रा का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। इसी तरह, हालांकि, विदेश यात्रा से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करने की शर्त एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे निस्संदेह इस मामले में अग्रिम जमानत के अनुदान के लिए एक शर्त के रूप में जोड़ा गया था। ... .. अधिक से अधिक, विदेश यात्रा से पहले अनुमति प्राप्त करने की शर्त को विनियमित किया जा सकता था, पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता था।”

20. इस न्यायालय ने पहले भी कई आदेश पारित किए हैं, जिनमें जमानत पर रिहा किए गए आरोपी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है। गणपति रामनाथ बनाम बिहार राज्य 9 में, इस न्यायालय ने एक आरोपी-आवेदक को चिकित्सा उपचार के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी, अपने पिछले जमानत आदेश को संशोधित करते हुए, यह देखते हुए कि आवेदक ने चिकित्सा आवश्यकता के आधार पर छह बार न्यायालय की अनुमति से विदेश यात्रा की थी और वापस लौटा था। के. मोहम्मद बनाम केरल राज्य में, इस न्यायालय ने आरोपी-अपीलकर्ता को पारिवारिक स्थिति की आपात स्थिति में मिलने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी। तरुण त्रिखा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में, इस न्यायालय ने आरोपी-याचिकाकर्ता को अपने रोजगार से संबंधित इंडोनेशिया यात्रा की अनुमति दी और काम पूरा होने के बाद वापस लौटने की अनुमति दी। पीताम प्रधान बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में, इस न्यायालय ने अग्रिम जमानत देते समय, याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा की अनुमति दी, यह देखते हुए कि उसकी नौकरी के लिए उसे बार-बार विदेश यात्रा करने की आवश्यकता थी और यदि उसे विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती तो उसकी नौकरी चली जाती।”





17. उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा दर्ज किया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्तमान कार्यवाही का मूल है। वर्तमान मामले में 15.05.2024 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आरोप का सार यह है कि उत्तरवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया जा रहा था। हालांकि, यह न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यात्मक पहलू पर विचार करने का इच्छुक नहीं है। यह नोट करना पर्याप्त होगा कि वर्तमान याचिकाकर्ता को 24.01.2024 को विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा जमानत दी गई थी। इस न्यायालय को यह तय करना है कि याचिकाकर्ता को भारत से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी जाए या नहीं।
18. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के भारत से बाहर अपने रोजगार के लिए यात्रा करने पर रोक नहीं होना चाहिए। जमानत देते समय अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों को आपराधिक न्याय के प्रवर्तन में सार्वजनिक हित और आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। मानवाधिकार और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की सुरक्षा को ऐसी शर्तों के लगाने से मायावी नहीं बनाया जाना चाहिए जो आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने, जांच के उचित पाठ्यक्रम और अंततः एक निष्पक्ष मुकदमे को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अनुपातहीन हों।
19. विवाद के मूल और इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाएगी तो वह न्याय से भागने की संभावना है, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता एक भारतीय नागरिक है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट है। यह सच है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन यह न्यायालय की राय में, विशेष रूप से जब उसे अपने रोजगार के क्रम में भारत से बाहर जाने की आवश्यकता है, तो उसे विदेश यात्रा करने से रोकना नहीं चाहिए।



20. इस प्रकार, यह न्यायालय इस राय में है कि विदेश यात्रा की अनुमति के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन अदालत और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को उसके द्वारा पहले से लिखित रूप में दिए गए समय के लिए भारत से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।
21. तदनुसार, याचिकाकर्ता को भारत से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि वह यात्रा की तारीख से पहले अदालत के समक्ष यह बयान दे कि वह उसके द्वारा दिए गए समय की समाप्ति के बाद भारत वापस आएगा, और वह संबंधित अदालत के समक्ष सभी सुनवाई की तारीखों पर उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से विशेष रूप से छूट न दी जाए। बयान यात्रा शुरू करने से पहले अदालत के समक्ष दाखिल किया जाएगा।
22. विविध आपराधिक याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है।



सही/  
रविन्द्र कुमार अग्रवाल  
न्यायाधीश



**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

